दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शनिवार 12 जून 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 252

देश में संक्रमण से मौतों के आंकड़े पर नहीं लगा ब्रेक, 24 घंटे में कोरोन के 91,702 नए मामले, 3,403 मरीजों की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में भले ही पिछले चार दिन से कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले एक लाख से कम आ रहे हों, लेकिन कोरोना से होने वाली दैनिक मौतें अभी तक डरा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 91,702 नए मामले सामने आए। जबकि 3,403 मरीज कोरोना की जंग हार गये और उसके काल का ग्रास बन गये। वहीं दूसरी तरफ इस एक दिन में नए मामलों से कहीं ज्यादा 1,34,580 मरीजों ने इस कोरोना वायरस को मात देकर इस जंग को जीता है और उपचाराधीन मरीजों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में लगातार चौथे दिन 24 घंटे में कोविड-19 के एक लाख से कम 91,702 नए मामले सामने आए, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,92,74,823 हो गई है। वहीं इस दौरान 3,403 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,63,079 हो गई। इस प्रकार कोविड-19 से मत्यु दर 1.24 प्रतिशत है। जबकि नमूनों के संक्रमित आने की दैनिक दर भी कम होकर 4.49 प्रतिशत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में उपचाराधीन मरीजों की 46,281 संख्या भी कम होकर 11,21,671 हो गई है, जो कुल मामलों का 3.83 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मामलों में कुल 46,281 की कमी आई है। देश में अभी तक कुल 2,77,90,073 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर भी बढ़कर 94.93 प्रतिशत हो गई है। कोविड-19 से मत्यु दर 1.24 प्रतिशत है।

24.60 करोड़ लोगों को लगा टीका

आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 32,74,672 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 24,60,85,649 हुआ। नमूनों के संक्रमित आने की दैनिक दर 4.49 प्रतिशत है। पिछले 18 दिन से संक्रमण की दैनिक दर 10 प्रतिशत से कम बनी हुई है। वहीं, संक्रमण की साप्ताहिक दर भी कम होकर 5.14 प्रतिशत हो गई है। संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या लगातार 29वें दिन संक्रमण के नए मामलों से अधिक रही। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोविड-19 रोधी टीकों की खुराक लेने वाले लाभार्थियों में 10024046 स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं जिन्होंने पहली खुराक लगवा ली है जबकि 6928432 स्वास्थ्य कर्मी टीके की दूसरी खुराक भी लगवा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि 45-60 आयुवर्ग के 73973962 और 11726702 लाभार्थी क्रमशः टीके की पहली और दूसरी खुराक ले चुके हैं। जबकि 60 साल से ज्यादा आयुवर्ग के 6189877 और 19633935 लाभार्थी क्रमशः टीके की पहली और दूसरी खुराक ले चुके हैं। बृहस्पतिवार को टीके की 3032675 खुराक लाभार्थियों को दी गई।

टीके की बर्बादी रोकने पर बल

भारत सरकार ने कहा है कि टीकाकरण करने वाले व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि हर वॉयल (शीशी) को खोलने की तारीख और समय नोट करें। सभी वैक्सीन वॉयल को खुलने के चार घंटे के अंदर उपयोग कर लेना चाहिए। इसलिए, वैक्सीन की बर्बादी एक फीसदी या उससे कम होने की उम्मीद बिल्कुल भी अनुचित नहीं है। यह तार्किक है और इसे प्राप्त किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण एवं खास

डिवाइडर से टकराई बाइक, युवक-युवती की मौत

जयपुर (आरएनएस)। सोडाला थाना इलाके में स्थित एलिवेटेड रोड पर तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में एक युवक और युवती की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों की शिनाख्त कर शव मोर्चरी में रखवाया। जहां उनका पोस्टमार्टम कर परिजनों के हवाले कर दिया गया। इस मामले की जांच पड़ताल सड़क दुर्घटना थाना दक्षिण द्वारा की जा रही है। सड़क दुर्घटना थाना दक्षिण थानाधिकारी शिवदयाल ने बताया कि हादसा सुबह करीब छह बजे सोडाला थाना इलाके में स्थित एलिवेटेड रोड के घुमाव पर हुआ था। इस हादसे में बाइक सवार निखिल पालीवाल (24) निवासी झोटवाड़ा और करिश्मा (24) निवासी प्रताप नगर की मौत हो गई। प्रारम्भिक जांच पड़ताल में सामने आया कि दोनो की मृतक नागौर जिले के रहने वाले है और शुक्रवार सुबह बाइक से घुमने निकले थे। इस दौरान उनकी तेज रफ्तार बाइक एलिवेटड रोड स्थित डिवाइडर से टकरा गई और दोनों गंभीर रुप से घायल हो गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

यूपी में दो बहनों से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में पांच गिरफ्तार

लखीमपुर (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में तीन बहनों को बंधक बनाने और उनमें से दो के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 18, 20 और 22 साल की बहनें, जो मजदूरी करती हैं, 4 जून को फूलबिहार में मोहन कुमार नाम के शख्स के खेत पर काम करने गई थीं। कुमार ने चार अज्ञात व्यक्तियों को भी खेत में बुलाया था। जब लड़कियों ने दिन के अंत में अपनी मजदूरी मांगी, तो कुमार और अन्य ने उन्हें बंद कर दिया और बाद में दो बहनों के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने शुरू में माना कि शिकायत पैसे के विवाद के कारण की गई थी, फूलबिहार पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई। बहनों को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और उनके बयान दर्ज किए गए। लड़कियों ने सभी आरोपियों की पहचान कर ली है। लखीमपुर खीरी के एसएसपी विजय ढुल ने कहा कि मामले में आगे की जांच अभी जारी है।

दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने कोर्ट में कहा, आसाराम को जमानत मिलने से हमें जान का खतरा

नई दिल्ली (आरएनएस)। दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने जेल में बंद आसाराम बापू की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अधिवक्ता के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि आसाराम अत्यधिक प्रभावशाली हैं और उनके राजनीतिक संबंध हैं और साथ ही आसाराम के पास लाखों अंधभक्त हैं। पीड़िता के पिता ने अपनी याचिका में कहा है कि आसाराम ने हत्यारे कार्तिक हलदर को हायर किया था, जिसने चश्मदीदों को मार डाला और हमला किया। उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि बापू ने हत्या करने के आदेश दिए थे। पीड़िता के पिता ने अपनी याचिका में दलील दी कि सुनवाई के दौरान उसे और उसके परिवार के सदस्यों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। याचिका में पीड़िता के पिता ने दावा करते हुए कहा है कि 10 चश्मदीदों पर हमला किया जा चुका है और उनमें से तीन लोगों की मौत हो चुकी है। आशंका जताई गई है कि अगर आसाराम को जमानत दी जाती है तो वह दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिवार से बदला लेगा। याचिका में कहा गया है कि किराए के हत्यारे हलदर ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि उसने आसाराम के आदेश पर प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी अखिल गुप्ता को गोली मार दी थी और उत्तर प्रदेश पुलिस ने अभी तक उससे पूछताछ या गिरफ्तार नहीं किया है। याचिका में जमानत का पुरजोर विरोध करते हुए कहा गया है कि आसाराम उनकी बेटी और परिवार के सदस्यों को मार सकता है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम ने हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद एक आयुर्वेद केंद्र में इलाज के लिए जमानत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है। राजस्थान सरकार ने भी उसकी जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि आसाराम इलाज कराने की आड़ में अपनी हिरासत की जगह बदलना चाहता है।

कोरोना वैक्सीन एंटीबॉडी बनाने के साथ शरीर में दूसरे दुष्प्रभावों को भी करता है कम

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश के अधिसंख्य लोगों में सिर्फ यही जानकारी है कि कोविड का टीका लगाने से शरीर में कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगती हैं। जबकि हकीकत में सिर्फ ऐसा ही नहीं है। कोविड का टीका न सिर्फ शरीर में एंटीबॉडी बनाता है बल्कि उन कोशिकाओं को भी मजबूत करता है जो शरीर के अन्य हिस्से के ज़रूरी भागों में बीमारी की वजह से कमजोर होने लगती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी वजह से टीका किसी भी बीमारी में न सिर्फ कारगर है बल्कि जीवन को बचाता है।

आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक और कोविड के इलाज पर नजर रखने वाले डॉक्टर समीरन पांडा कहते हैं कि कोविड की वैक्सीन से दो तरह की इम्युनिटी बनती है। पहली इम्युनिटी न्यूट्रिलाइजिंग एंटीबॉडी होती है, जो वायरस के शरीर में मौजूद होने की वजह से शरीर की किसी कोशिका को संक्रमित करने और अंदरूनी विकास को प्रभावित करने से रोकने लगती है। इसलिए टीका लगाने के साथ जो एंटीबॉडी बनती है उसको न्यूट्रिलाइजिंग एंटीबॉडी कहते हैं। जो उस रोग के खिलाफ शरीर के अंदर लड़ती है उसका दुष्प्रभाव रोक देती है। डॉक्टर समीरन कहते हैं कि सामान्यतया लोगों को यही पता होता है कि टीका एंटीबॉडी बनाता है। डॉक्टर पांडा का कहना है कि एंटीबॉडी के अलावा सेल मीडिएटेड इम्युनिटी भी टीका लगाने से बढ़ती है।

कोरोना वैक्सीन के लिए मुस्लिमों को समझाएंगे मौलवी

» मोदी सरकार ने शुरू किया जागरूकता अभियान

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना की वैक्सीन को लेकर लोगों के दिल दिमाग से डर खत्म करना सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। वहीं, मुस्लिम समुदाय में इस झिझक पर अल्प संख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि टीकाकरण को लेकर गलतफहमी भगाने के लिए, हज समितियों, वक्फ बोर्ड, केंद्रीय वक्फ परिषद और स्वयं सहायता समूहों को जान है तो जहान है अभियान में शामिल किया जा रहा है।

नकवी ने कहा कि इस बीच, मुंबई के एक एनजीओ और मुस्लिम मौलवियों ने शहर में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए हाथ मिलाया है। एनजीओ भामला फाउंडेशन ने मुंबई में विभिन्न मस्जिद समितियों के मौलाना और मौलवियों को एक साथ लाया और उनसे झुग्गी बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह किया। ये ग्रुप न केवल जागरूकता फैलाएगा बल्कि लोगों के लिए टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक करने की व्यवस्था भी करेगा। इस संगठन ने अपने अभियान की सारी व्यवस्था के लिए एक वॉर रूम भी तैयार किया है। भामला फाउंडेशन के अध्यक्ष आसिफ भामला ने एएनआई से बात करते हुए कहा, इस पहल से मुस्लिम समुदाय में कोविड टीकाकरण को लेकर विश्वास पैदा होगा। उन्होंने कहा कि कई लोग कुछ गलतफहमियों के कारण टीकाकरण से डर रहे हैं, इसलिए हमने मौलाना और मौलवियों को शामिल किया जो लोगों को समझा सकते हैं। हम चाहते हैं कि वे मुसलमानों के बीच इस झिझक को दूर करें। अभियान में भाग लेने वाले मौलवी मौलाना तबरेज़ ने कहा कि लोगों में कोरोना वैक्सीन के लिए कई गलत धारणाएं है। कुछ का कहना है कि वे इसे लेने के बाद मर जाएंगे, जबकि अन्य साइड इफेक्ट के बारे में चिंतित हैं। इस गलत सूचना को दूर करने के लिए हम दो अलग-अलग शिफ्टों में घर-घर जाकर टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में तुरंत लागू की जाए वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना : सुको

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिये है कि वन नेशन-वन राशन कार्ड को तुरंत लागू किया जाए। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को जारी आदेश में यह भी टिप्पणी की गई कि इसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को जारी आदेश में कहा कि कोई बहाना नहीं, तुरंत लागू करें वन नेशन-वन राशन कार्ड। अदालत ने यह भी कहा है कि आप एक या अन्य समस्या का हवाला नहीं दे सकते हैं। यह प्रवासी मजदूरों के लिए है। वहीं उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों द्वारा उठाए गए समस्याओं पर अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान असंगठित मजदूरों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में दिक्कत आई थी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही मजदूर विभिन्न सरकारों द्वारा चलाई जा रही लाभकारी स्कीमों का फायदा उठा सकते थे। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है। गौरतलब है कि इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना से राज्य को बाहर रखने की बात कही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को इसे तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना को लेकर केंद्र सरकार का तर्क रहा है कि इस योजना के तहत पूरे देश में पीडीएस धारकों को देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि इसके बाद नौकरी या अन्य वजहों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले लोग सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होंगे।

हाल ही में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच घर घर राशन योजना को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना तुरंत लागू करने के लिए कहा था। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा था कि इस योजना को अविलंब लागू करें जिससे दिल्ली के कम से कम दस लाख आप्रवासी श्रमिकों को इसका तुरंत लाभ मिल सके। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वह जनकल्याणकारी नीतियों के मसले पर मूकदर्शक नहीं रहेगा। नीतियों की न्यायिक समीक्षा उसका कर्तव्य है। बता दें कि अब तक आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब और ओडिशा समेत अब तक कई राज्यों ने वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना को लागू किया है।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार की संभावनाएं बढ़ी

नई दिल्ली (आरएनएस)। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिपरिषद विस्तार इस महीने हो सकता है। मंत्रिपरिषद में फेरबदल और बदलाव के लिए 23 मंत्रालयों का चयन किया गया है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल के लिए जल्द बुलाया जा सकता है। वहीं राजग में सहयोगी दलों की हिस्सेदारी को लेकर दलों से विचार विमर्श किया जा रहा है।

देश में कोरोना काल के दौरान कई मंत्रियों के निधन और अन्य कारणों से सरकार में दर्जन भर मंत्रियों के पास एक से अधिक मंत्रालयों का जिम्मा है। ऐसे मंत्रियों के काम का बोझ करने के मकसद से मंत्रिमंडल मे विस्तार होने की संभावनाएं प्रबल हो री हैं। सूत्रों के अनुसार सोनोवाल को दिल्ली बुलाया गया था। जबकि विमर्श के लिए ही सिंधिया विदेश यात्रा से पहले हफ्ते ही वापस लौट आए थे। इस बीच उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम के कारण विमर्श में देरी हुई। अब कहा जा रहा है कि जल्द ही इन नेताओं के साथ विमर्श का सिलसिला शुरू किया जाएगा। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी मंत्रिपरिषद में शामिल होने पर अपनी सहमति दे दी है। हालांकि जदयू को कैबिनेट में किस तरह का प्रतिनिधित्व मिलेगा, इस पर चर्चा होनी बाकी है। सूत्रों का कहना है कि जदयू को कैबिनेट और राज्यमंत्री का एक-एक पद दिया जाएगा।

पेट्रोल-डीजलों की कीमतों पर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल ने भी साधा मोदी सरकार पर निशाना

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में आज दिल्ली तथा देश के दूसरे राज्यों के अलग-अलग इलाकों में विभिन्न पेट्रोल पंपों के निकट सांकेतिक प्रदर्शन किया।

पार्टी का दावा है कि इस दौरान कोरोना वायरस से संबंधित प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र सरकार पर महामारी के समय पेट्रोल-डीजल पर कर बढ़ाकर जनता के साथ 'लूट' का आरोप लगाया।

राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जीडीपी गिर रही है। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। आखिर भाजपा कितने तरीके से भारत को लूटेगी?

प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि महामारी के दौरान मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर कर वसूले = पूरे 2.74 लाख करोड़ रुपये। इस पैसे से पूरे भारत को टीका (67000 करोड़ रुपये), 718 जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र, 29 राज्यों में एम्स की स्थापना और 25 करोड़ गरीबों को छह - छह हजार रूपये की मदद मिल सकती थी। मगर मिला कुछ भी नहीं।

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल घोड़ा-गाड़ी पर सवार होकर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के निकट पेट्रोल पंप पहुंचे।

वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली तत्कालीन संप्रग सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय कर 9.20 रुपये था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में इसके बढ़ाकर 32 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी बंद करनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया जाए। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने राजेंद्र नगर और जनपथ में पेट्रोप पंपों के निकट विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने भी विरोध स्वरूप घोड़ा-गाड़ी की सवारी की। कांग्रेस की युवा इकाई भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी जनपथ रोड स्थित पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी ने आरोप लगाया कि महामारी के दौरान भाजपा का लूट चक्र रूकने का नाम नहीं ले रहा है। 4 मई से 9 जून के बीच पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 21 बार बढ़ोतरी हुई है। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम कम हैं, ऐसे समय में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाना देशवासियों के साथ अवैध वसूली जैसा कृत्य है।